

+

C

M

Y

अब हर शुक्रवार को पेंड्री में होगी न्यायिक सुनवाई, केन्द्रीय क्षेत्र के ग्रामीणों को बड़ी राहत

नरेन्द्रगढ़ (अभिकावाणी समाचार)। एसडीएम कार्यालय केन्द्रीय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार तहसील केन्द्रीय अंतर्गत उप-तहसील पेंड्री के पटवारी हल्का क्रमिक 9, 11, 12 एवं 13 के सम्पूर्ण ग्रामीणों से संबंधित राज्य प्रकरणों की सुनवाई अब सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को उप-तहसील पेंड्री स्थित कैप कोर्ट में की जाएगी। न्यायालयीन कार्य के संपादन हेतु तहसीलदार केन्द्रीय को निर्देशित किया गया है कि वे नियमित रूप से हर शुक्रवार पेंड्री पहुँचकर मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। शासन के इस निर्णय से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी, उन्हें अब न्याय के लिए परसूरा तहसील कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। यह व्यवस्था ग्रामीणों की समय और संस्थापन की बचत के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में सहायक सिद्ध होगी। शासन द्वारा उठाया गया यह कदम स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता, त्वरित न्याय और जन सुविधा के दृष्टि से एक सकारात्मक प्रयास है, जिसकी क्षेत्रीय सार्विक और जनप्रतिनिधियों द्वारा सराहना की जा रही है।

अभिकावाणी

न्यूज गैलरी

राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा योजना के तहत बीज वितरण का सफल कार्यक्रम



कोरिया बैकुंठपुर। जिले के जनपद पंचायत बैकुंठपुर क्षेत्र के ग्राम चिल्का, पिपिया, रंगो, धरमपुर, के किसानों को राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा अनाज कोषों, रागी एवं दलहन क्षेत्र विस्तार हेतु अहर्ह बीज निशुल्क का वितरण किया गया। कोरिया जिले में कुपि विभाग शासन की योजनाओं के तहत खाद बीज वितरण में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है बावजूद इसके आगर जिले के किसान जनहितकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसान हाईब्रिड जैसे महंगे बीज चक्रकर में फँसकर के अपना नुकसान कर रही हैं। उपरोक्त कार्यक्रम में जनपद सदस्य, सार्वजनिक जवकार पंच सहित ग्रामीण किसान उपस्थित रहे।

शाला प्रवेशोत्सव के अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, राज्य में कोरिया जिला बना शिक्षा का अग्रगूत



कोरिया बैकुंठपुर। शिक्षा सत्र २०२४-२५ में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले कोरिया जिले के मेधावी विद्यार्थियों को आज शाला प्रवेशोत्सव के अवसर पर सम्मानित किया गया। यह सम्मान समाग्रह बैकुंठपुर के जिला पंचायत ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ, अभिभावक, शिक्षक व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस परिणामवी अवसर पर छात्रीसमूह माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दर्शनी व बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी सफलता के लिए सम्मानित किया गया।

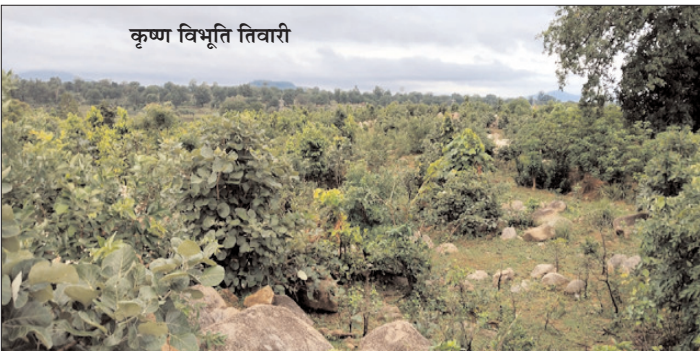
कोरिया जिले की उपलब्धियाँ - दसवीं कक्षा में वर्ष २०२३-२४ में नवां स्थान जबकि २०२४-२५ में राज्य में चौथा स्थान प्राप्त किया गया। बारहवीं कक्षा में वर्ष २०२३-२४ में सातवां स्थान में था जबकि २०२४-२५ में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जिले का परीक्षा परिणाम में दर्शनी में १२.३३ प्रतिशत और बारहवीं में १२.२२ प्रतिशत रहा जबकि राज्य में दर्शनी में ७६ प्रतिशत, बारहवीं में ८१ प्रतिशत परीक्षा परिणाम था। इस तरह कोरिया जिला राज्य औसत से काफी अगेत रहा।

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कड़ी ये बातें - कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा, 'यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों की सतत निगरानी और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी १००० के तहत प्रैक्टिस परीक्षा से पहले कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाएँ चलाई गईं और ऑनलाइन शिक्षा की भी सुविधित व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य शासन द्वारा निःशुल्क उपकरणों का वितरण किया जा रहा है, जिन्हें स्कूल को के माध्यम से ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को अपने वाले वर्षों में कोरिया जिला और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। शिक्षकों और छात्रों के सामूहिक प्रयासों से जिले को राज्य में शीर्ष स्थान पर लाने का संकल्प लिया गया है। इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डॉ. अनुसूचित चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैरवार, उपमुख्य श्रीमती चंदन राजवाड़े, जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सोयावती कुमरो, मुख्या शिक्षा, श्रीमती सोनीता सोनिया, जनपद अध्यक्ष उदय सिंह, विद्यार्थक प्रतिनिधि पत्र प्रताप मावी, वरिष्ठ नगरिक शैलेश शिवार, कृष्ण विहारी जासवाल कार्यक्रम में सोनहट व बैकुंठपुर से आए छात्र, शिक्षक व पालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

प्राकृतिक साल जंगल को बचाने की जरूरत: सलका, सलवा क्षेत्र में संरक्षण की ग्रामीणों ने मांग की



कृष्ण विभूति तिवारी



कोरिया बैकुंठपुर। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के समीप स्थित ग्राम पंचायत सलका, सलवा के समीप शासन प्रशासन के द्वारा जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बावजूद इसके योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के पूर्व कलेक्टर अमीर अली के द्वारा लगभग ५० एकड़ राज्य की जमीन में वृक्षारोपण करवाया गया। इस वृक्षारोपण से आम आदमी को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है

ऊपर से मालू का डेरा बनकर रह गया है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा जिला स्तरीय स्टैंडियम का निर्माण लगभग ५ करोड़ की लागत से कई गई लेकिन स्टैंडियम खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। इस स्टैंडियम से कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा है। इस स्टैंडियम में ग्रामीणों के द्वारा पशु बांधने का काम कर रहे हैं। अरु वनों से यहाँ प्राकृतिक रूप से साल वृक्षों का विनाश हुआ है। यह वन क्षेत्र न केवल पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि ग्रामीणों के

लिए जलवायु संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र का भी आधार है। स्थानीय लोगों एवं पर्वारण प्रेमियों की चिंत का मुख्य कारण यह है कि इस जंगल की सुरक्षा और देखरेख का कोई स्थायी प्रबंध नहीं है। राज्य भूमि होने के कारण वन विभाग की सीधी निगरानी से यह क्षेत्र वादर है, जिसके कारण वहाँ पर अतिक्रमण और अवेध कटाई की घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। ग्रामीणों द्वारा जलाक लकड़ी एवं निजी उपयोग हेतु पेड़ों की कटाई खुलेआम की जा रही है,

जिससे धीरे-धीरे जंगल की हरियाली समाप्त हो रही है। जानकारों का कहना है कि साल वृक्ष का प्राकृतिक रूप से उगना इस क्षेत्र की जैव विविधता के लिए अनमोल स्रोत है। साल के जंगल वृक्ष जल संचयन में सहायक होते हैं और मिट्टी के कटाव को भी नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, यह वन्य जीवों का भी प्राकृतिक आवास है। यदि इस क्षेत्र को संरक्षित नहीं किया गया तो अनेक वारे वनों में यह पूरी हरित संपदा समाप्त हो सकती है। स्थानीय पर्यावरण

मुख्यमंत्री से केन्द्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री दुहे ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में केन्द्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र दुहे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्य में कोयला खनन एवं उत्पादन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में राज्य में कोयला उत्पादन, खनन कार्यों की प्रगति, श्रमिकों से जुड़ी सुविधाओं एवं विकास कार्यों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोयला एवं ऊर्जा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को साकार करने में सहायता मिलेगी। श्री साय ने इस दौरान सीएसआर मद की राशि का उपयोग अधिक से अधिक जनकल्याणकारी कार्यों में करने में राज्य में विशेष रूप से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री ए. रघुनंदन, एसईसीए के मुख्य महाप्रबंधक श्री हरिजित दुहन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

न्यायधानी बिलासपुर में केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू के हाथों ट्रैफिक नैन महेश मिश्रा को मिला पुलिस गौरव देशभक्त सम्मान

दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय गायन, नृत्य, टैलेट, फैशन शो एवं सम्मान समारोह में निभाई मंच संचालक की भूमिका

कोरिया बैकुंठपुर। बिलासपुर स्थित डॉ. जेठू साहू के रिसेंट में टीवीबी मीडिया द्वारा २८ एवं २९ जून को दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय गायन, नृत्य, टैलेट, फैशन शो प्रतियोगिता एवं विविध क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें कोरिया जिले के बालावत में पदस्थ लाल नारायण मिश्रा को भी पुलिस गौरव देशभक्त सम्मान से सम्मानित किया गया। गौरवलेन है कि नारायण मिश्रा निःस्वार्थ भाव से निरंतर यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित करते हेतु न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश एवं देश स्तर पर जाने जाते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी यातायात जागरूकता अभियान संचालित करते रहे हैं। केन्द्रीय राज्यमंत्री भारत गायन, नृत्य, टैलेट, फैशन शो प्रतियोगिता एवं विविध क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें कोरिया जिले के बालावत में पदस्थ लाल नारायण मिश्रा को भी पुलिस गौरव देशभक्त सम्मान से सम्मानित किया गया। गौरवलेन है कि नारायण मिश्रा निःस्वार्थ भाव से निरंतर यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित करते हेतु न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश एवं देश स्तर पर जाने जाते हैं



हुआ करती आपकी जरा सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। वाहन दुर्घटना अपने आप नहीं

रखने में सहयोग प्रदान करें। उक्त दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नगर निगम बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विद्यानी, राज्य सरकार के अखिल भारतीय कांस्य कमेटी प्रदेश प्रभारी उर प्रदेश व गुजरात फिलोसोफी चंद श्रीवास, शुक्ला उग्रस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशलपूर्वक मंच संचालन कोरिया जिले के नावक महेश मिश्रा ने किया। सफल आयोजन एवं सम्मान हेतु श्री मिश्रा ने टीवीबी मीडिया की स्टेट डायरेक्टर पुष्पा साहू एवं मीडिया प्रभारी अमित कुमार का विशेष आभार व्यक्त किया।

छत्तीसगढ़ में ओबीसी महासभा कोरिया ने सौपा ज्ञापन : सामाजिक न्याय और समानुपातिक हिस्सेदारी की मांग

कोरिया बैकुंठपुर - छत्तीसगढ़ के (विभिन्न जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) महासभा ने अपने समुदाय के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक विस्तृत ज्ञापन सौपा है। यह ज्ञापन कलेक्टर कोरिया के माध्यम से महाप्रतिमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, और मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया गया है। ओबीसी महासभा ने विगत कई वर्षों से हर माह ज्ञापन सौपा करने मांगों को उठाया है, किंतु राष्ट्रीय जनगणना, २ दिवसीय २०२२ की पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्तक्षेप जैसे ज्वलंत मुद्दे अभी तक अनुसूद्ध हैं।

प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू के मार्गदर्शन और प्रदेश सचिव कृष्णा प्रजापति के उपस्थिति में सौपा एवं इस ज्ञापन में ओबीसी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षणिक उत्थान के लिए २३ बिंदुओं पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर ओबीसी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष शान नारायण साहू, रवि शंकर राजवाड़े, कुतुबिना प्रजापति, कृष्ण राजवाड़े, हरिहर साहू, शिखरदास राजवाड़े, संचालित राजवाड़े, डी एल भास्कर, आनंद राजवाड़े, रामदास साहू, राजू गोयनकर, स्वतंत्र मोहोविषा सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख बिंदु: १.-राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की गणना: ओबीसी महासभा ने मांग की है कि लीबल राष्ट्रीय जनगणना शीघ्र आयोजित की जाए, जिसमें ओबीसी समुदाय की जनसंख्या का स्पष्ट आंकड़ा शामिल हो। छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय की जनसंख्या ५.२२ होने का अनुमान है, और आधिकारिक आंकड़ों के अभाव में उनकी समानुपातिक हिस्सेदारी प्रभावित हो रही है। २.-समानुपातिक आरक्षण: ओबीसी समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान करने की मांग की गई है। यह सामाजिक न्याय और समानुपातिक समाज की स्थापना के लिए आवश्यक कदम है। ३.-कौमिलेवर और ५०८ कैप्सिंग की समाप्ति: कौमिलेवर की अवधारणा को परिवार और समाज के लिए घिघनकारी बजाते हुए इसे समाप्त करने की मांग की गई है। साथ ही, आरक्षण पर ५०८ की सीमा के अंतर्धानिक करार दूर होइ इसे हटाने का अनुरोध किया गया है। ४.-५०८ ओबीसी आरक्षण: छत्तीसगढ़ में २०७ ओबीसी आरक्षण को तत्काल लागू करने और पिछले ३२ वर्षों के

बैकलॉग निवृत्तियों को भरने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, २ दिवसीय २०२२ की पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर महामहिम राज्यपाल के हस्तक्षेप के लिए शासन से त्वरित कार्यवाई का अनुरोध किया गया है। ५.-मंडल कमीशन की अनुसूची: मंडल कमीशन की सभी विधिवार्ता को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की गई है, जो ओबीसी समुदाय के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। ६.-सविधान की नवी अनुसूची में शामिल करना: २७३ ओबीसी आरक्षण को देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू करने और भारत सरकार द्वारा अयोध्या पारित कर इसे सविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। ७.-छात्रावसों का प्रावधान: छत्तीसगढ़ के सभी तहसील मुख्यालयों में ओबीसी के लिए समुदायिक पुस्तकालय और प्री-मैट्रिक छात्रावास स्थापित करने की मांग की गई है। ८.-न्यायमार्गदर्शन आयोग की रिपोर्ट लागू करना: कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में स्वामिनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई है, ताकि किसानों को उचित समर्थन मिल सके। ९.-बैकलॉग निवृत्तियों: केन्द्र और राज्य की शासकीय संस्थाओं में रिक्त



पदों पर बैकलॉग निवृत्तियों प्रदान करने की मांग की गई है, जिससे ओबीसी समुदाय के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। १०.-शिक्षा युक्तियुक्तकरण का निरन्तरिकरण: हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा किए गए स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बतौर हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई है। ११.-छात्रवृत्ति में समानता: ओबीसी समुदाय के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में वित्तीयता को दूर कर अनुसूचित जाति और जनजाति की भाति समान स्तरों और

दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग की गई है। १२.-कुशल कर्मचारी की अनिवार्यता: छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय सेवा के पदों पर कुशल कर्मचारी की अनिवार्यता से संबंधित करने की मांग की गई है। १३.-ओबीसी प्रमाण पत्र प्रक्रिया का सरलीकरण: सामाजिक प्रार्थनात्मक (ओबीसी) प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने की मांग की गई है। १४.-जट्ट में समानुपातिक प्रमाणन: ओबीसी के समाज विकास की उपलब्धता: किसानों को समय के अभाव में प्राधान्य देने की मांग की गई है।

१५.-पृथक ओबीसी विभाग की स्थापना: कर्नाटक, केरल, और अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में ओबीसी के लिए पृथक विभाग स्थापित करने की मांग की गई है। १६.-ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने की मांग की गई है। १७.-किसानों के लिए खाद-बीज कार्यक्रम को सरल करने की मांग की गई है। १८.-किसानों के लिए खाद-बीज कार्यक्रम को सरल करने की मांग की गई है। १९.-किसानों के लिए खाद-बीज कार्यक्रम को सरल करने की मांग की गई है। २०.-किसानों के लिए खाद-बीज कार्यक्रम को सरल करने की मांग की गई है।

धान खेती १ नवंबर से शुरू करने की मांग की गई है। *१८.-साक्षात्कार प्रक्रिया समाप्त करना: आंध्र प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों पर १६ साक्षात्कार प्रक्रिया के बंद करने की मांग की गई है। *१९.-वनभूमि पट्टा: २००५ से शासकीय भूमि पर कब्जाधारी और निवासरत ओबीसी समुदाय के लोगों को वनभूमि पट्टा प्रदान करने की मांग की गई है। *२०.-अनिर्णित कर्मचारियों का निर्णयितकरण: सचिव, लेसमेंट, मानव, दीर्घक वेतन बोनी, और ठेका कर्मचारियों की नियमित करने की मांग की गई है। *२१.-पृथक ओबीसी विभाग की स्थापना: कर्नाटक, केरल, और अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में ओबीसी के लिए पृथक विभाग स्थापित करने की मांग की गई है। *२२.-ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने की मांग की गई है। *२३.-ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने की मांग की गई है। *२४.-ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने की मांग की गई है। *२५.-ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल करने की मांग की गई है।

कदम - ओबीसी महासभा ने अपने ज्ञापन में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रेंद को हड़ो माने जाने वाले ओबीसी समुदाय को सामाजिक न्याय प्रदान करना समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है। यह ज्ञापन न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में ओबीसी समुदाय के लिए नीतिगत बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है। *नेतृत्व और एकजुटता - ज्ञापन सौपने के इस कार्यक्रम में ओबीसी महासभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। राधेश्याम साहू ने कहा, रहमास संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक ओबीसी समुदाय को उठना हक नहीं मिल जाता। हर परसुरा सोई ने जोर देकर कहा कि शासन को इन मांगों पर तत्काल कार्यवाई करनी चाहिए, ताकि ओबीसी समुदाय का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। *नियमित की दिशा - ओबीसी महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि उनके मांगों पर शीघ्र कार्यवाई नहीं की गई, तो वे अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। यह ज्ञापन न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में ओबीसी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और तेज रस्सी और आर्थिक न्याय की दिशा में उनकी लड़ाई को मजबूत करता है।



बांस से आरणी कमार जनजाति के जीवन में हरियाली, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत मिलेगा प्रशिक्षण

00 बांस से सशक्त होगी आजीविका, सुरक्षित रहेगा पर्यावरण, 00 बांस से आदिवासी परिवारों को मिलेगा रोजगार और आत्मनिर्भरता

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय परिवारों को खेती-बाड़ी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इस दिशा में बांस आधारित योजनाएं मील का पत्थर साबित हो रही हैं। आदिवासी संस्कृति में बांस का विशेष महत्व रहा है और अब यह आजीविका के सशक्त साधन के रूप में उभर रहा है। प्रदेश सरकार बांस के माध्यम से आदिवासी परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और बांस के उत्पादों को बाजार तक सीधी पहुंच के माध्यम से बढ़ावा देना चाहती है। इस अभियान को उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि परिस्थितियों को भी संतुलित रहेगा।



धरती जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले पिछड़ी कमार जनजाति के परिवारों के जीवन में बांस अब खुशहाली और हरियाली लेकर आएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित

धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के धरती जिले के कमार सहित अन्य जनजातीय परिवारों को बांस की खेती और बांस कला का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान को उद्देश्य जनजातीय परिवारों को पारंपरिक

आजीविका के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों से जोड़कर उनकी आय को सुदृढ़ करना है। बांस न केवल पर्यावरण के लिए वरदान है, बल्कि यह आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने में सक्षम है। बांस उत्पादों की देश-विदेश में

बढ़ती मांग को देखते हुए जनजातीय परिवारों को न केवल खेती बल्कि उत्पाद निर्माण, डिजाइनिंग और विपणन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। धरती के कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा ने बताया कि जिले के गंगरेल

और तुमरावाहरा क्षेत्र में बांस की खेती के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बांस विशेष रूप से आदिवासी परिवारों के लिए एक अच्छा विकल्प है। बांस के अनेक उपयोग हैं, जैसे फर्नीचर, लैम्प, पेन स्टैंड, झाड़ू, सूपा, आकर्षक टोकरियां, प्लेटनुमा बोर्वा, पानी की बोतल, दूधब्रश और बांस ज्वेलरी बनाने की जानकारी दी जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि जिले में बांस का आदिवासी परिवारों को आय का मुख्य स्रोत बनाने के लिए बैचु ब्लेज, आर्टिफिशियल काई, बैचु एकुरीओ, किसान बैचु क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बांस की खेती और बांस कारीगरों को उनके कौशल उत्थान के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित बांस कला केन्द्र में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने किया मंत्रालय के पंचम तल में नवीन सभागार का लोकार्पण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नया रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन के सेक्रेटरी ब्लॉक के पंचम तल पर निर्मित नवीन सभागार का लोकार्पण किया। 13.90 करोड़ रुपये की कुल लागत से निर्मित यह भव्य सभागार सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। 6450 वर्गफुट क्षेत्र में बने इस कॉन्फ्रेंस हॉल को बैठक क्षमता 185 सीटों की है। सभागार आंतरिक विद्युतीकरण, अग्निशमन व्यवस्था, वातानुकूलन, ऑडियो-विजुअल प्रणाली, आंतरिक साज-सज्जा तथा फर्नीचर सहित सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री



राज्य विचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सुविधाओं से सुसज्जित है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री

90 प्रतिशत विकलांगों को घरमै विकलांग सेवा ने दिया झीलचेयर

रायपुर। खोरा (अधनपुर) के लगभग 90 प्रतिशत विकलांगों को उनके कौशल उत्थान के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित बांस कला केन्द्र में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।



ओझा ने बताया कि वसंत साहू पिछले 8 वर्ष से स्यादुलत कोई ईंजरी से प्रसिद्ध हैं एवं लगभग पूरा समय बिस्तर पर लेटे रहते हैं। उनकी आवश्यकता को देखते हुए उनके भाई नरसिंह को सोमवार को एक नई झीलचेयर प्रदान किया गया। इस अवसर पर जेपी अखिलेश, रोशन बहादुर सिंह, किंअश, पार्थ, नरसिंह साहू उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पथलगांव में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 4 करोड़ की राशि स्वीकृत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के फलस्वरूप पथलगांव में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से 4 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। कुछ दिन पूर्व ही नगर पालिका जशपुर के वार्ड क्रमांक 16 में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 6 करोड़ 76 लाख 55 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।



लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं

शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक सुव्यवस्थित मंच प्राप्त होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे नाटक, संगीत, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ एवं सरकारी कार्यक्रमों का सफल प्रतिपादों को अपनी कला और विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता को प्रोत्साहन

मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जन सुविधा आधारित आधोसंरचना विकास को नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री की पहल पर किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, महिलाओं और आम नागरिकों को आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए विभिन्न विकास कार्यों को प्रोत्साहन स्वीकृति मिल रही है और योजनाएं भी तेजी से क्रियान्वित हो रही हैं।

माजपा प्रदेश मीडिया प्रमारी विमनानी मिले केद्रीय मंत्री मांडविया व सांसद सुधांशु से

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रमारी अमित विमनानी ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान सोमवार को केद्रीय मंत्री खेल, युवा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मनसुख मांडविया एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी से दिल्ली में मुलाकात कर छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया तथा राष्ट्रीय परिषद में राजनीतिक विषयों पर चर्चा की।

मंत्रालय मनसुख मांडविया एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी से दिल्ली में मुलाकात कर छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया तथा राष्ट्रीय परिषद में राजनीतिक विषयों पर चर्चा की।

मंत्रालय मनसुख मांडविया एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी से दिल्ली में मुलाकात कर छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया तथा राष्ट्रीय परिषद में राजनीतिक विषयों पर चर्चा की।

77 वे सीए दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

सीए दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ....

सी.ए. अरुण कुमार गुप्ता
आज & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सूरजपुर

प्रदीप कुमार अग्रवाल (सीटू)

सौजन्य - श्री जगदम्बा स्टोन क्रेसर, केतका रोड

सूरजपुर (छ.ग.) मो. 9754005400